RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 336

दि. 09.04.2026,

गुरुवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

खौफ से राहत की ओर: 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका-ईरान संघर्षविराम, क्या टिक पाएगी यह शांति?

जीएनएस)। मध्य पूर्व में बीते चालीस दिनों से जारी भय, विस्फोटों और अनिश्चितता के बीच आखिरकार एक ऐसी सुबह आई है, जिसने करोड़ों लोगों को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच लगातार बढ़ते सैन्य टकराव के बाद अब 14 दिनों के संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। यह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि थके हुए क्षेत्र के लिए अस्थायी सुकून का वह पल है, जहां लोग पहली बार बिना सायरन की आवाज के आसमान की ओर देख पा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता वैश्विक कूटनीति के नए समीकरणों की भी झलक देता है, जहां पारंपरिक शक्ति संतुलन के बीच नई ताकतें निर्णायक भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। इस संघर्षविराम का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि बीते 40 दिनों में जिस स्तर की तबाही और मानव क्षति हुई है, उसने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, इस युद्ध में अब तक 1,900 से अधिक ईरानी नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि लेबनान में 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी सेना के 13 जवानों की मौत ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया। हजारों मिसाइलों, ड्रोन हमलों और बमबारी के बीच आम नागरिकों का जीवन जैसे थम गया था। सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई जैसे देशों में लोग लगातार डर के साए में जी रहे थे, जहां हर पल यह आशंका बनी रहती थी कि अगला हमला कब और कहां होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमलों ने जिस आग को भड़काया, वह जल्दी बुझने वाली नहीं थी। शुरुआती रणनीति भले ही त्वरित और निर्णायक जीत की रही हो, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए। ईरान ने न केवल अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब दिया, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। इसका असर यह हुआ कि पूरे मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और लाखों लोग विभिन्न देशों में फंस गए।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका होर्मुज जलडमरूमध्य की रही, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। ईरान ने इस रणनीतिक मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। भारत समेत कई देशों में इसका सीधा असर देखने को मिला, जहां एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई। हालांकि सरकारों ने लगातार आश्वासन दिया कि भंडार पर्याप्त हैं, लेकिन 'पैनिक बाइंग' की स्थिति ने यह साफ कर दिया कि वैश्विक संघर्ष का असर आम लोगों की रसोई तक पहुंचता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह युद्ध उम्मीद से कहीं अधिक जटिल साबित हुआ। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि ईरान जल्दी झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने लगातार हमलों के बावजूद अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखी और जवाबी कार्रवाई जारी रखी। यही वह बिंदु था, जहां अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। लंबे युद्ध में फंसने का खतरा, वैश्विक दबाव और आर्थिक प्रभावों ने अंततः अमेरिका को संघर्षविराम के लिए तैयार किया।

इस समझौते के पीछे चीन और पाकिस्तान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। चीन, जो पहले ही वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, इस मध्यस्थता के जरिए एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने इस वार्ता को अपने कूटनीतिक प्रभाव के विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया है। इस घटनाक्रम ने यह संकेत भी दिया है कि आने वाले समय में वैश्विक संकटों के समाधान में पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के साथ-साथ एशियाई देशों की भूमिका भी बढ़ेगी।

हालांकि संघर्षविराम के बावजूद कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या यह शांति केवल 14 दिनों तक सीमित रहेगी, या इससे आगे भी स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ेंगे? क्या अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की शर्तों को स्वीकार कर पाएंगे, या यह केवल एक अस्थायी विराम है जिसके बाद फिर से संघर्ष भड़क सकता है? इजरायल की स्थिति भी इस पूरे समीकरण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इस युद्ध में और अधिक रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता था।

इस संघर्ष के दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, वह था वैश्विक आर्थिक समीकरणों में बदलाव। अमेरिका के दबदबे वाले डॉलर सिस्टम को चुनौती देते हुए ईरान और चीन ने तेल व्यापार में युआन का इस्तेमाल बढ़ाया। यह कदम भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा को बदल सकता है और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। अगर यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है, तो इसका असर न केवल अमेरिका, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, आर्थिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ईरान ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह से लंबे समय तक मुकाबला किया, उसने यह साबित कर दिया कि छोटे देश भी बड़े शक्ति संतुलन को चुनौती दे सकते हैं।

अब जब संघर्षविराम लागू हो चुका है, तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि यह अस्थायी शांति स्थायी समाधान की दिशा में पहला कदम साबित हो। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अगर दोनों पक्ष संवाद के जरिए अपने मतभेद सुलझाने में सफल होते हैं, तो यह न केवल मध्य पूर्व, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा।

फिलहाल, यह सुबह शांति की है, राहत की है और उम्मीद की है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में शांति बनाए रखना आसान नहीं होता। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह 14 दिन का संघर्षविराम स्थायी शांति में बदल पाएगा, या यह केवल एक तूफान से पहले की खामोशी साबित होगा।

बढ़ता खतरा, कड़ा संदेश: बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने राज्यों को चेताया

जीएनएस)। देश में तेजी से बढ़ रही बाल तस्करी की घटनाओं ने न्यायपालिका को गहरी चिंता में डाल दिया है और इसी गंभीरता को देखते हुए Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या को तुरंत और प्रभावी ढंग से नहीं रोका गया, तो यह स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो सकती है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी केवल एक औपचारिक निर्देश नहीं, बल्कि उस सामाजिक संकट की ओर संकेत है, जो देश के भविष्य—यानी बच्चों—को सीधे प्रभावित कर रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि बाल तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कई मामलों में यह संगठित अपराध का रूप ले चुकी हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और अधिक गहराती जाएगी। यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने की आवश्यकता है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाल तस्करी के पीछे सक्रिय गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में संगठित रूप से काम कर रहे हैं। ये गिरोह बच्चों को बहला-फुसलाकर या जबरन

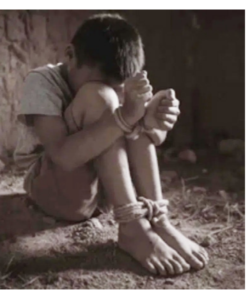

ले जाकर उन्हें मजदूरी, भीख मंगवाने, अवैध गतिविधियों या शोषण के अन्य रूपों में धकेल देते हैं। ऐसे में यह केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के खिलाफ एक गंभीर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारों और उनके गृह विभागों को सक्रिय और सतर्क भूमिका निभानी होगी। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायालय एक सीमा तक ही हस्तक्षेप कर सकता है। निगरानी और दिशा-निर्देश देना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई राज्य सरकारों, पुलिस प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को ही करनी होगी। इस संदर्भ में अदालत ने गृह सचिवों से कहा कि वे इस समस्या को केवल एक आंकड़े के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक गंभीर मानवीय संकट के रूप में समझें और उसी के अनुरूप कार्य करें। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि प्रतिदिन बाल तस्करी से जुड़ी नई-नई रिपोर्टें सामने आ रही हैं। हालांकि, कुछ मामलों में बच्चों को छुड़ाने की खबरें भी मिलती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि यदि इच्छाशक्ति और समन्वित प्रयास हो, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। अदालत ने इसी बिंदु को रेखांकित करते हुए कहा कि समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, तेज कार्रवाई और प्रभावी रणनीति की जरूरत है।

इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बाल तस्करी केवल एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की कमी, सीमित संसाधन और कभी-कभी लापरवाही भी इस समस्या को बढ़ाने में योगदान देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप एक चेतावनी के साथ-साथ एक अवसर भी है, जिसमें राज्य सरकारें मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल तस्करी को रोकने के लिए केवल कानून बनाना या सख्त सजा देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, गरीब और कमजोर परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, और बच्चों की शिक्षा व संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, पुलिस और जांच एजेंसियों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से लैस करना भी जरूरी है, ताकि वे ऐसे अपराधों का समय रहते पता लगा सकें और उन्हें रोक सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर अपनी निगरानी जारी रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर और कड़े निर्देश भी जारी करेगा। यह संकेत है कि आने वाले समय में इस विषय पर न्यायपालिका की सक्रियता और बढ़ सकती है।

अंततः, यह मामला केवल सरकारों या अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाता है। जब तक समाज का हर वर्ग—चाहे वह प्रशासन हो, नागरिक हों या सामाजिक संगठन—इस समस्या के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास नहीं करेगा, तब तक इसे पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती एक चेतावनी जरूर है, लेकिन साथ ही यह एक आह्वान भी है कि अब समय आ गया है जब इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएं।

आस्था बनाम न्यायिक दखल: सबरीमाला सुनवाई में केंद्र के तर्कों ने फिर छेड़ी संवैधानिक बहस

जीएनएस)। देश के सबसे संवेदनशील और बहुचर्चित धार्मिक विवादों में से एक सबरीमाला प्रकरण एक बार फिर न्यायिक बहस के केंद्र में आ गया है, जहां Supreme Court of India में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आस्था और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को लेकर महत्वपूर्ण तर्क रखे। इस बहस ने न केवल कानून और धर्म के बीच संतुलन के सवाल को फिर जीवंत किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कितनी जटिल और बहुस्तरीय है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने जोर देकर कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आस्था सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि आस्था का क्षेत्र तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति की आंतरिक मान्यता और धार्मिक विश्वास का विषय है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से केंद्र ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि अदालतों को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।

अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने 1972 के चर्चित मामले Seshammal vs State of Tamil Nadu का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि

राज्य की कोई कार्रवाई धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं में हस्तक्षेप करती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत अवैध हो सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रसिद्ध विधिवेत्ता नानी पालखीवाला के तर्कों का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया था कि सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म की मूल पहचान को समाप्त नहीं किया जा सकता।

इस पूरे घटनाक्रम में जस्टिस B V Nagarathna की टिप्पणियां भी बेहद महत्वपूर्ण रहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुधार के नाम पर किसी धर्म को "खोखला" नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि न्यायपालिका भी इस संतुलन को लेकर सजग है कि सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक रेखा बनी रहनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान "धार्मिक संप्रदाय" की परिभाषा को लेकर भी गहन चर्चा हुई। सॉलिसिटर जनरल ने S.P. Mittal vs Union of India का हवाला देते हुए बताया कि किसी धार्मिक संप्रदाय को परिभाषित करने के लिए तीन प्रमुख शर्तें होती हैं—पहला, साझा आस्था या विश्वास प्रणाली; दूसरा, एक संगठित ढांचा; और तीसरा, एक विशिष्ट पहचान या नाम। हालांकि, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस परिभाषा को सीमित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कई बार अलग-अलग आस्थाओं के लोग एक ही धार्मिक स्थल से जुड़े हो सकते हैं।

सबरीमाला मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू याचिकाकर्ताओं की वैधता को लेकर उठा। जस्टिस नागरत्ना ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मूल याचिकाकर्ता स्वयं मंदिर के भक्त नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि जब किसी सीधे प्रभावित पक्ष ने इस प्रथा को चुनौती नहीं दी, तो ऐसे में बाहरी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर अदालत किस आधार पर विचार कर सकती है। यह सवाल न केवल इस मामले तक सीमित है, बल्कि जनहित याचिकाओं के दायरे और उनकी सीमाओं पर भी एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने यह उल्लेख किया कि यह याचिका Indian Young Lawyers Association द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने पूर्व में दिए गए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अल्पमत निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी बाहरी व्यक्ति को किसी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह तर्क इस विचार को मजबूत करता है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल उन लोगों तक सीमित होना चाहिए, जो उस परंपरा का हिस्सा हैं। इस सुनवाई ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र में आस्था, अधिकार और न्याय के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ओर संविधान सभी नागरिकों को समानता और अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर वह धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। ऐसे में अदालतों को हर मामले में यह तय करना पड़ता है कि किस स्थिति में हस्तक्षेप उचित है और कब नहीं।

सबरीमाला विवाद केवल एक मंदिर या एक प्रथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न का प्रतिनिधित्व करता है कि आधुनिक समाज में परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार के तर्कों और अदालत की टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर और गहन विचार-विमर्श होगा, जो भारतीय न्याय व्यवस्था और सामाजिक ढांचे दोनों के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकता है। अंततः, यह मामला केवल कानून की व्याख्या का नहीं, बल्कि समाज की आत्मा से जुड़े उस सवाल का है, जहां आस्था और अधिकार आमने-सामने खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय चाहे जो भी हो, यह बहस लंबे समय तक देश के बौद्धिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनी रहेगी।

विकास का महाप्लान: मोदी कैबिनेट के फैसलों से ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों को नई ताकत

जीएनएस)। देश की विकास यात्रा में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले मील के पत्थर बन जाते हैं। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में लिए गए निर्णय भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनका असर देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, शहरी परिवहन और कृषि व्यवस्था पर व्यापक रूप से दिखाई देने वाला है। यह बैठक एक तरह से उस व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब रही, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, संतुलित क्षेत्रीय विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती को केंद्र में रखा गया है। सबसे प्रमुख और बहुचर्चित निर्णय राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना से जुड़ा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी देते हुए इसे बढ़ाकर लगभग 79,459 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही Hindustan Petroleum Corporation Limited द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे कुल निवेश 19,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह रिफाइनरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी, जहां पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ पॉलीप्रोपिलीन, एलएलडीपीई, एचडीपीई और बेंजीन जैसे महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता कम कर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

राजस्थान जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र में इस तरह की विशाल परियोजना का स्थापित होना औद्योगिकीकरण को नई गति देगा। निर्माण कार्य के दौरान ही हजारों लोगों को रोजगार मिल चुका है और भविष्य में भी इससे जुड़े सहायक उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह केवल एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि एक औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में योगदान देगा। इस परियोजना की वाणिज्यिक शुरुआत एक जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई है, जिससे देश की ऊर्जा क्षमता में एक महत्वपूर्ण इजाफा होने की उम्मीद है।

ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के इसी प्रयास के तहत मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। पहली परियोजना कालई द्वितीय जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट होगी और इस पर लगभग 14,105 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना लोहित नदी पर बनाई जाएगी और इससे हर वर्ष 4,852 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। दूसरी परियोजना कमला जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता 1,720 मेगावाट होगी और इस पर करीब 26,079 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे हर साल 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी, बल्कि राष्ट्रीय ग्रिड को भी संतुलन मिलेगा।

इन जल विद्युत परियोजनाओं का महत्व केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इनके निर्माण से सड़कों, पुलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी होगा, जिससे स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो हर साल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है।

शहरी परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें 36 स्टेशन शामिल होंगे। इसकी कुल लागत लगभग 13,037 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। यह कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डा, टोंक रोड और शहर के अन्य प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। इससे जयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में यातायात की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। जयपुर मेट्रो का यह विस्तार केवल यात्रा को सुगम बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सार्वजनिक परिवहन के बढ़ते उपयोग से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और शहर का समग्र पर्यावरण बेहतर होगा। इस परियोजना को वर्ष 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो भविष्य के शहरी विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समयसीमा है।

कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। खरीफ सत्र 2026 के लिए फास्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए लगभग 41,533 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जो यह दर्शाती है कि सरकार किसानों की लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने के प्रति गंभीर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा।

कुल मिलाकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में लिए गए फैसले एक व्यापक और संतुलित विकास रणनीति का हिस्सा हैं। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी परिवहन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ निवेश बढ़ाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है। ये निर्णय न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आधार भी तैयार करेंगे।

संपादकीय

मंडी पोर्टलों की बाधा

कहने को तो देश डिजिटल क्रांति के दौर में पहुंच चुका है और वित्तीय लेनदेन से लेकर तमाम क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक वरदान साबित हो सकती है। लेकिन हमें यह मानकर चलना चाहिए कि देश का परंपरागत किसान डिजिटल सुविधाओं के उपयोग में खुद को सहज महसूस नहीं करता। आधुनिक डिजिटल तकनीक का प्रयोग नई पीढ़ी की सोच के अनुरूप है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इसके उपयोग में खुद को असहज पाती है। कमोबेश किसानों के कल्याण के लिए बनाये गए मंडी पोर्टलों पर भी यही बात लागू होती है। जाहिरा तौर पर किसानों के लिये मंडी पोर्टलों का उपयोग आसान होना चाहिए। बाकायदा किसानों को डिजिटल साक्षर बनाने की मुहिम चलाने की जरूरत भी है। सही मायनों में डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि उपजों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना था। लेकिन हरियाणा में जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। दरअसल, हम एक आम किसान से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह शहरी लोगों की तरह पोर्टलों, पासवर्डों और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों के जाल का सहजता से उपयोग कर सके। यही वजह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ उठाने के लिये उसे एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर की मंडियों से द ट्रिब्यून में प्रकाशित हालिया रिपोर्टों से एक जैसा पैटर्न नजर आया है। अब राज्य में फसलों की बिक्री के लिये अनिवार्य पोर्टल- ई-खरीद और मेरी फसल,मेरा ब्योरा यानी एमएफएमबी- साइट क्रैश, डेटा विसंगतियों और सत्यापन की विफलताओं से ग्रस्त है। जिससे कई तरह की समस्याओं से किसानों को रूबरू होना पड़ रहा है। यहां तक कि कई जिलों में, किसानों को गेट पास तक नहीं दिए गए हैं। वजह यह बतायी जा रही है कि किसानों का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है। कई बार अंतिम व महत्वपूर्ण क्षणों में सर्वर ने काम नहीं किया। जिसका खमियाजा फसल बेचने आने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल, ऐसी अनेक तकनीकी जटिलताओं के परिणाम तात्कालिक व गंभीर बताये जाते हैं। किसानों की फसल तो बिक्री के लिये तैयार है, लेकिन कतिपय कारणों से उसे मंडियों में प्रवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है किसान अपने खून-पसीने की फसल निजी व्यापारियों को बेचने को विवश हो जाते हैं। किसान की मजबूरी ये होती है कि वह जल्द से जल्द फसल बेचना चाहता है। उसे अपने पहले के खर्च निकालने हैं और अगली फसल की तैयारी करनी है। जिसके चलते वह तुरंत भुगतान की आस में कम दाम में भी व्यापारियों को फसल बेचने को बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं, लेकिन फसल की आवक का एक छोटा हिस्सा ही खरीद पायी हैं। जो फसल खरीद के वायदे और वास्तविक तैयारी के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। कुछ आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। विशेष रूप से, हरियाणा में गेहूं की खरीद को 80 लाख टन से घटाकर 72 लाख टन करने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उन्हें आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि जो अनाज एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है, उसे किसान व्यापारियों को एमएसपी से 400 से पांच सौ रुपये कम दाम पर बेचने को मजबूर है। यानी एमएसपी के मूल उद्देश्य के विपरीत यह किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि डिजिटलीकरण का लक्ष्य व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। लेकिन इस प्रणाली की उपयोगिता तभी है जब सर्वर ठीक से काम कर रहा हो। साथ ही लोग इसका उपयोग बेहतर ढंग से करना जानते हों। यह प्रक्रिया छोटे और गरीब व निरक्षर किसानों को प्रोसेस से बाहर कर देती है। जिनकी सेवा का दावा व्यवस्था अक्सर करती है। एक विसंगति यह भी कि इसमें कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। पोर्टल के फेल होने पर खरीद रुक जाती है। यदि एमएसपी का लाभ कमजोर डिजिटल प्रणाली की वजह से किसान को नहीं मिलता, तो यह किसानों का सुरक्षा कवच नहीं रह जाता है।

पंजाब व हरियाणा में मुश्किल दौर की आहट

> खाड़ी युद्ध के प्रभावों से देश का 'अन्न भंडार' कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा के लोगों के सामने अब अपने अस्तित्व के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। खाद संकट से खेती की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं निर्यात की चुनौती बढ़ने के साथ श्रमिक वर्ग भी प्रभावित होगा।

किसान तरनतारन का हो या रोहतक का या फिर बिहार अथवा यूपी का कोई प्रवासी मज़दूर, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में किया गया सैन्य 'दखल' एक दिन उसकी ज़िंदगी पर इतना गहरा असर डालेगा कि उसके जीवन-यापन की लागत पर बन आएगी। भले ही अब इस्राइल और अमेरिका ईरान पर बमबारी बंद कर भी दें, लेकिन अगर राज्यों के चुनावों के बाद तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और इसका असर भारतभर में महसूस किया जा रहा है। भले ही सरकार आर्थिक नुकसान के असर को ढांपने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। होर्मुज़ जलडमरू के बंद होने से दुनियाभर के तेल और गैस बाज़ारों में उथल-पुथल मच गई है, जिसके चलते महंगाई तेज़ी से बढ़ी है और भोजन एवं उर्वरकों की किल्लत पैदा हो गई है। यह संकट केवल गैस सिलेंडरों के लिए मची अफरा-तफरी या किसी शहर अथवा इलाके के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लगी लंबी लाइनों तक ही सीमित नहीं है। भले ही सरकार पर्याप्त आपूर्ति सुचारु रखने का कितना भी भरोसा क्यों न दिला रही हो। इससे भी बड़ा खतरा है पूरे देश में आर्थिक मंदी छाने का, रोज़गार के अवसर छिन जाने का, और लोगों की आमदनी कम हो जाने का।

पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार में सत्तासीन राजनेता, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर लगाम कसने, आपूर्ति शृंखलाओं को सुचारु बनाए रखने, विशेष रूप से कृषि व उद्योगों को वैश्विक ईंधन कीमतों के इस भीषण प्रहार से बचाने की योजनाएं बनाने की बजाय, अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरने में ही खर्च कर रहे हैं। भारत द्वारा अपने पारंपरिक शुभचिंतकों—ईरान और रूस को बिना सोच-विचार किए तज देने, और हमलावर मुल्कों—अमेरिका व इस्राइल का साथ देने से स्थिति में और ज़्यादा बिगाड़ आया है। देश को न केवल तेल और गैस के आयात के लिए, बल्कि उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन-आधारित यूरिया खरीदने के लिए भी अब कहीं ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यूरिया उत्पादन में 30 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। चीन के बाद, भारत दुनियाभर में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। आपूर्ति में किसी भी मात्रा की कटौती का सीधा मतलब है कृषि उत्पादन में कमी आना और किसानों की आमदनी में गिरावट। देश का 'अन्न भंडार' कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा के कई लोगों के सामने अब अपने अस्तित्व को बचाए रखने का संकट खड़ा हो सकता है। कर्ज़ चुकाना और भी मुश्किल हो सकता है, जिससे लोगों का मानसिक तनाव और भी बढ़ जाएगा। रसोई गैस सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण प्रवासी मज़दूरों का जो पलायन शुरू हुआ है, अगर उसे समय रहते प्रभावी ढंग से नहीं थामा गया, तो यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है; जिसका सीधा असर इन दोनों ही राज्यों में गेहूं की कटाई और धान की रोपाई पर पड़ सकता है। खाद की कमी से अन्न उत्पादन घट जाएगा, जिससे खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी। इससे खासकर उन परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, जिन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार का अनाज और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही, आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के परिणामवश कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। मध्यम वर्ग की आय या तो स्थिर हो जाएगी या फिर उसमें गिरावट आएगी। रोज़गार योजना में किए गए बदलाव के कारण पहले से ही दिहाड़ी और ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए रोज़गार के अवसर कम हो चुके हैं। अब उन्हें काम मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा।

विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर और वस्तु बाज़ारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसके कारण रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि आयात, विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई करना और भी महंगा हो जाएगा। जैसे-जैसे लोगों के जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ेगा, आय में असमानता और सामाजिक चिंताएं बढ़ेंगी। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बनी यह विकट परिस्थिति, मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर सूबों—पंजाब और हरियाणा—के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि इन राज्यों में कीमतों में आया झटका ज्यादा खतरनाक है। हरियाणा में सरकार भाजपा की होने के कारण, हो सकता है केंद्र सरकार कुछ अतिरिक्त मदद कर दे और वह इस स्थिति से बेहतर ढंग से निपट पाए; लेकिन पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। पंजाब में भाजपा के नेता, भगवंत मान सरकार को घेरने के लिए चुन-चुनकर मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन उन मसलों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं जिन पर केंद्र सरकार का ध्यान दिलवाये जाने की ज़रूरत होती है। ताज़ा बजट से पता चलता है कि पंजाब की विकास दर 6.1 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह लड़खड़ाती रही, तो राज्य पर वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। अगर पश्चिम एशिया का टकराव लंबा खिंचता है तो हाल ही में हुए निवेशक सम्मेलन में किए गए 55,000 करोड़ रुपये मूल्य निवेश के कई वादे सिर्फ़ कागज़ों पर ही रह जाएंगे।

पंजाब से उच्चकोटि का बासमती चावल और खेल के सामान का निर्यात का ज़्यादातर हिस्सा होर्मुज़ जलडमरू से होकर गुज़रता है, और लगभग 60 लाख टन माल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। बीमा और शिपिंग की दरें आसमान छूने के साथ-साथ, निर्यात में अनुमानित 50 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करने वाली कंपनियां, भुगतान में देरी होने के कारण काफी मुश्किल में हैं। परेशान निर्यातक चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत 'वस्तु-विनिमय प्रणाली' शुरू करे जैसे कि कच्चे तेल के बदले बासमती चावल का लेन-देन।

लेकिन भयावहता इतनी होने के बावजूद भी पंजाब की अलग-अलग पार्टियों के नेताओं को उनकी नींद से नहीं जगा पाई है। अवसरवादिता और अल्प-कालिक चुनावी फ़ायदों में पले-बढ़े ये नेता, आने वाले संकट के काले बादलों से बेखबर होकर, अपनी ढर्रे की राजनीति जारी रखे हुए हैं। किसी नेता की असली परख संकट के समय ही होती है। पिछले साल जब पंजाब में बाढ़ आई थी, तब भाजपा के कुछ मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, आश्वासन दिए थे, लेकिन समय बीतने के साथ वे सब कुछ भूल गए। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की राहत राशि पहुंचने का अभी भी इंतज़ार है। अब एक और संकट सिर पर खड़ा हो गया है और पंजाब में भाजपा के नेता इससे मुंह मोड़ रहे हैं।

समस्या यह है कि दिल्ली में बैठा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, और न ही किसी मुद्दे पर उनकी राय लेना ज़रूरी समझता है। भाजपा की प्राथमिकताओं की सूची में पंजाब का स्थान कहीं बहुत नीचे है। वे चंडीगढ़ स्थित अपने दफ़्तर के बाहर हुए एक धमाके पर भी खूब शोर मचाते हैं; वे इसके लिए पंजाब सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। भूल जाते हैं कि किसी भी केंद्र-शासित प्रदेश में शांति भंग होने की स्थिति में, इसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं के अपने केंद्रीय गृह मंत्री की बनती है।

जहां तक आप, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की बात है तो इनमें शायद ही कोई ऐसा पाएदार नेता है, जो किसानों और निर्यातकों की ओर से हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार से कोई सार्थक प्रतिक्रिया हासिल कर पाए। इसलिए, यह जिम्मेवारी पूरी तरह से भाजपा नेतृत्व के पसंदीदा नेताओं—जैसे कि हरदीप पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, तरनजीत सिंह संधू और पार्टी में हाल ही में शामिल हुए वकील एचएस फूलका की बनती है कि वे प्रधानमंत्री को इस बात के लिए राज़ी करें कि वे पश्चिम बंगाल चुनावों से इतर पंजाब के बारे में भी विचार करें। पंजाब का जो जायज़ हक़ है, उसे दिलाने की कोशिश करें।

प्रेरणा

जब शिक्षा बन गई मिशन: अंबेडकर की लगन से मिलती दिशा

समाज में बदलाव की सबसे मजबूत नींव शिक्षा को माना जाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन न रहकर एक बड़े उद्देश्य का माध्यम बन जाए। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने इस सत्य को न केवल समझा, बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह उतारकर दिखाया। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन इसी विचार का सशक्त उदाहरण है। उनका छात्र जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे मिशन की तैयारी थी, जिसका उद्देश्य पूरे समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना था।

जब वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंचे, तो उनके सामने अनेक अवसर और चुनौतियां दोनों मौजूद थीं। एक ओर वहां का आधुनिक शैक्षणिक वातावरण था, जो उन्हें ज्ञान अर्जित करने के अनगिनत साधन प्रदान करता था, वहीं दूसरी ओर उनके मन में अपने समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी भी थी। वे यह भली-भांति जानते थे कि उनकी शिक्षा केवल उनके जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के जीवन को सुधारने के लिए है, जो वर्षों से सामाजिक अन्याय का सामना कर रहे थे।

उनकी दिनचर्या इस बात का प्रमाण थी कि वे अपने उद्देश्य के प्रति कितने गंभीर थे। वे रोजाना सबसे पहले पुस्तकालय पहुंचते और उसके बंद होने तक लगातार अध्ययन में लगे रहते। उनके लिए समय का हर एक क्षण अमूल्य था और वे उसे पूरी तरह ज्ञान अर्जित करने में लगाते थे। जहां अन्य छात्र पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन में भी समय बिताते थे, वहीं अंबेडकर ने अपने जीवन को पूरी तरह अनुशासन और समर्पण के मार्ग पर केंद्रित कर लिया था।

उनकी यह आदत केवल मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके भीतर की उस गहरी सोच का प्रतीक थी, जो उन्हें सामान्य से अलग बनाती थी। वे यह समझ चुके थे कि यदि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उन्हें अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। यही कारण था कि उन्होंने किसी भी प्रकार के विचलन को अपने रास्ते में आने नहीं दिया।

एक दिन पुस्तकालय के एक कर्मचारी ने उनकी इस निरंतरता को देखकर उनसे प्रश्न किया। उसने कहा कि उनकी उम्र के अधिकांश छात्र पढ़ाई के साथ-साथ जीवन का आनंद भी लेते हैं, लेकिन वे हमेशा किताबों में डूबे रहते हैं। इस पर अंबेडकर ने जो उत्तर दिया, वह उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए पढ़ रहे हैं। उनके इस उत्तर ने उस कर्मचारी को ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया, जो इस घटना के बारे में जानता है।

यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हमारी प्राथमिकताएं अपने आप तय हो जाती हैं। अंबेडकर के लिए पढ़ाई केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा माध्यम था, जिसके जरिए वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। उनकी यह सोच आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जब शिक्षा को अक्सर केवल एक करियर बनाने के साधन के रूप में देखा जाता है।

उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं, यदि हमारे भीतर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो। अंबेडकर ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में लिया और उसे अपनी ताकत में बदल दिया।

आज के युवाओं के लिए यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है। यह हमें बताती है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है।

इसके साथ ही, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हमारी सफलता का महत्व और भी बढ़ जाता है।

अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि हमारे पास सही सोच और दृढ़ संकल्प हो, तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह दिखाया कि शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदला जा सकता है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। यह हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची सफलता वही है, जो केवल हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। अंबेडकर ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाया और यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि अंबेडकर की शिक्षा यात्रा केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है, जो हमें अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देता है। उनका यह विचार कि "मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए पढ़ रहा हूं," आज भी हर विद्यार्थी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यदि हम इस सोच को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

गाजा और ईरान युद्ध के बाद अरब देशों का भरोसा अमेरिका से उठा, चीन-रूस पर बढ़ा

मध्य पूर्व आज बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का ज्वलंत उदाहरण बन चुका है। जिस अमेरिका ने दशकों तक इस क्षेत्र को अपनी रणनीतिक मुट्ठी में रखा, वही आज यहां अपनी पकड़ खोता नजर आ रहा है। पहले गाजा में तबाही और अब ईरान युद्ध से उपजे हालात अरब देशों को गहरी चिंता में डाल गये हैं। गाजा में हमले और ईरान युद्ध से लाखों लोग बेघर हुए, हजारों जिंदगियां खत्म हुईं और पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर फैल गया। इस सबसे अरब दुनिया के लोगों के दिल और दिमाग में बड़ा बदलाव आया है। हम आपको बता दें कि अरब दुनिया में अब अमेरिका के लिए भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। जनता उसे एक पक्षीय, अवसरवादी और नैतिक रूप से कमजोर शक्ति के रूप में देख रही है। इसके उलट चीन और रूस को अधिक संतुलित और भरोसेमंद विकल्प माना जाने लगा है। लोग अब यह मानने लगे हैं कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून की बात केवल तब करता है जब उसे फायदा हो। अरब देश यह भी देख रहे हैं कि गाजा अब भी मलबे में दबा है और वहां पुनर्निर्माण की कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। इसके अलावा, इस युद्ध की सबसे भारी कीमत खाड़ी देशों को चुकानी पड़ रही है। पर्यटन, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वह बुरी तरह हिल गया है। अनुमान है कि पर्यटन राजस्व में 13 अरब से 32 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट तब हो रही है जब 2024 में इन देशों ने पर्यटन से 120 अरब डॉलर का राजस्व कमाया था। इतना ही नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार अरब देशों को इस युद्ध से करीब 200 अरब डॉलर तक का कुल नुकसान हो सकता है। यानी यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संकट का संकेत है।

इसके अलावा, खाड़ी देशों ने दशकों तक अमेरिका को अपने यहां सैन्य अड्डे बनाने की अनुमति देकर यह भरोसा किया था कि इससे उनकी सुरक्षा मजबूत होगी और वह किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ईरान के साथ हालिया युद्ध ने इस धारणा को गहरे स्तर पर झकझोर दिया है। हकीकत यह सामने आई कि यही अमेरिकी अड्डे खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गए। ईरान ने सीधे तौर पर उन ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी मौजूदगी थी और इसके चलते हमले खाड़ी देशों की जमीन पर हुए। नतीजा यह हुआ कि नुकसान केवल अमेरिका का नहीं, बल्कि खाड़ी देशों का भी हुआ और उनकी सुरक्षित निवेश गंतव्य तथा स्थिर क्षेत्र की छवि को गहरा आघात पहुंचा। इसलिए सबसे गंभीर सवाल यह उठता है कि जब संकट की घड़ी आई तो अमेरिका अपने ही सैन्य अड्डों के आसपास स्थित देशों को पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सका। ऐसे में अब यह बहस तेज हो रही है कि क्या खाड़ी देश भविष्य में अमेरिका को अपने यहां सैन्य मौजूदगी जारी रखने देंगे या वह इस मॉडल पर पुनर्विचार करेंगे। यह घटनाक्रम पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि किसी बाहरी शक्ति को अपने भूभाग पर सैन्य अड्डे देने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है।

इसलिए मध्य पूर्व में आने वाले समय में रणनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अरब देश समझ रहे हैं कि अमेरिका की अगुवाई वाली व्यवस्था अब दरक रही है। अरब देश अब खुलकर या चुपचाप अपने विकल्प तलाश रहे हैं। चीन और रूस के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, व्यापारिक साझेदारियां गहरी हो रही हैं और नए बहुपक्षीय मंचों की ओर झुकाव साफ दिख रहा है। साथ ही खाड़ी देशों ने युद्ध से पहले अमेरिका को चेताया था, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। अब जब वह खुद नुकसान झेल रहे हैं, तो वह अपने निवेश और गठबंधनों पर दोबारा सोचने को मजबूर हैं।

देखा जाये तो अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इजराइल के प्रति अंध समर्थन बन चुकी है। अरब जनता इसे अन्याय और दोहरे मापदंड के रूप में देखती है। लोगों का मानना है कि अमेरिका ने न तो मानवाधिकारों की रक्षा की और न ही अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया। यही कारण है कि अब चीन को ज्यादा जिम्मेदार और संतुलित शक्ति माना जा रहा है। यह अमेरिका के प्रभाव के खत्म होने का संकेत है।

साथ ही इस पूरे संकट ने वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को भी पक्षपाती माना जा रहा है। लोगों का भरोसा नियम आधारित व्यवस्था से उठ रहा है। यह संकेत है कि दुनिया अब एक नई, बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां पश्चिम का प्रभुत्व कमजोर होगा। वैसे, अमेरिका के पास अभी भी मौका है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। अगर वह ईरान युद्ध को जल्द खत्म करता है और फिलिस्तीन मुद्दे पर न्यायपूर्ण रुख अपनाता है, तो कुछ हद तक अपनी साख बचा सकता है। लेकिन अगर वही नीतियां जारी रहीं, तो मध्य पूर्व में उसका प्रभाव इतिहास बन सकता है।

बहरहाल, अमेरिका की गिरती साख, खाड़ी देशों का आर्थिक संकट और बदलता जनमत यह साफ संकेत दे रहे हैं कि शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। अगर अब भी अमेरिका ने दिशा नहीं बदली, तो मध्य पूर्व में उसकी जगह कोई और लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अभियान

वायु में बसती आस्था: श्रीकालहस्ती की अदृश्य शक्ति का अलौकिक संसार

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थल ऐसे हैं, जहां पहुंचते ही मन, बुद्धि और आत्मा एक अलग ही अनुभूति से भर जाते हैं। आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित श्रीकालहस्ती मंदिर ऐसा ही एक पवित्र स्थल है, जहां की हवा में ही दिव्यता का स्पर्श महसूस होता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और ऊर्जा का ऐसा संगम है, जहां अदृश्य भी सजीव प्रतीत होता है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु यह अनुभव करता है कि मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे अपने सान्निध्य में ले रही हो।

श्रीकालहस्ती मंदिर को भगवान शिव के वायु स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। पंचभूत स्थलों में इसका विशेष स्थान है, जहां शिव के पांच मंदिर प्रकृति के पांच तत्वों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें श्रीकालहस्ती मंदिर वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन का आधार है और हर प्राणी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है।

जब कोई भक्त इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो उसे एक विशेष अनुभव होता है। वहां बिना किसी बाहरी स्रोत के भी एक हल्की हवा का प्रवाह महसूस होता है। यह हवा न केवल शरीर को स्पर्श करती है, बल्कि आत्मा को भी झकझोर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव अपने वायु स्वरूप में उपस्थित होकर भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। यह अनुभव इतना अनोखा होता है कि पहली बार आने वाला व्यक्ति भी इसे कभी नहीं भूल पाता।

मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी अपनी विशेषताओं के कारण अत्यंत अद्भुत माना जाता है। यह शिवलिंग वायु तत्व को समर्पित है और इसकी पूजा विशेष विधि-विधान के साथ की जाती है। मान्यता है कि इस शिवलिंग को कोई भी मानव सीधे स्पर्श नहीं करता, यहां तक कि पुजारी भी इसे हाथ नहीं लगाते। अभिषेक और पूजा केवल अनुष्ठानिक रूप से संपन्न होती है, जो इसकी पवित्रता और दिव्यता को और भी बढ़ा देती है।

श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास भी गहरा है कि यहां की पूजा और दर्शन से अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से हृदय, फेफड़े और पेट से संबंधित बीमारियों में राहत मिलने की मान्यता इस मंदिर को और भी विशिष्ट बनाती है। यह विश्वास केवल आस्था का परिणाम नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव है, जिसे यहां आने वाले लोग स्वयं महसूस करते हैं।

इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि इसका मूल स्वरूप पूर्व-वैदिक काल में एक छोटे से पूजा स्थल के रूप में था, जिसे स्थानीय जनजातियों द्वारा पूजित किया जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी ने किया था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। इन तीनों की भक्ति और समर्पण के कारण ही इस स्थान का नाम श्रीकालहस्ती पड़ा, जिसमें 'श्री' मकड़ी, 'काल' सांप और 'हस्ती' हाथी का प्रतीक है।

समय के साथ यह मंदिर कई राजवंशों के संरक्षण और योगदान से विकसित हुआ। पल्लव, चोल और विजयनगर जैसे शक्तिशाली राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया और इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। मंदिर की वास्तुकला में इन सभी कालों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विशाल गोपुरम, सुंदर मंडप और जटिल नक्काशी इस बात का प्रमाण हैं कि यह केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि कला और स्थापत्य का भी अद्वितीय उदाहरण है।

मंदिर का राजगोपुरम विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है, जिसकी ऊंचाई और भव्यता दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेती है। इसके अलावा मंदिर के विभिन्न मंडप, जैसे नंदी मंडप, राहु-केतु मंडप और कल्याण मंडप, अपनी-अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंडपों के स्तंभों पर की गई नक्काशी में रामायण, महाभारत और शिव पुराण की झलक मिलती है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि कला की दृष्टि से भी अनुपम हैं।

श्रीकालहस्ती मंदिर की एक और विशेषता इसका ग्रह दोष निवारण से जुड़ा होना है। यहां राहु-केतु पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसके लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि इस पूजा के माध्यम से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में सुख-समृद्धि लाई जा सकती है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो सर्प दोष, कालसर्प योग या अन्य ज्योतिषीय बाधाओं से परेशान होते हैं।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राहु और केतु ने भी यहां आकर भगवान शिव की आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें ग्रहों का दर्जा प्राप्त हुआ। यही कारण है कि यह स्थान उनके पूजन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहां होने वाली राहु-केतु पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह श्रद्धालुओं के लिए मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम है।

मंदिर में हर वर्ष मनाया जाने वाला कल्याणोत्सव भी अत्यंत भव्य और महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लोगों को अपनी परंपराओं और आस्था से जोड़ता है।

श्रीकालहस्ती मंदिर का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। यहां की हवा, यहां की ध्वनि और यहां की आस्था—सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो मन को शांति और आत्मा को संतोष प्रदान करता है।

आज के आधुनिक युग में, जब जीवन की भागदौड़ और तनाव ने लोगों को भीतर से थका दिया है, ऐसे में श्रीकालहस्ती जैसे स्थान हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति और संतुलन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब हम प्रकृति और आस्था के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है।

अंततः, श्रीकालहस्ती मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है—एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। यहां की हवा में जो दिव्यता है, वह हर उस व्यक्ति को स्पर्श करती है, जो सच्चे मन से यहां आता है। यही कारण है कि यह स्थान सदियों से आस्था, विश्वास और ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले समय में भी यह अपनी इसी विशेषता के कारण लोगों को आकर्षित करता रहेगा।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की पूर्व तैयारियों के निरीक्षण एवं अध्ययन के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम की पहली गुजरात यात्रा

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट से स्पोर्ट टीम ने गुजरात यात्रा का प्रारंभ किया
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए टाइम बाउंड, क्वालिटेटिव और इफेक्टिव प्लानिंग के मंत्र से शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को टीमवर्क से सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष ने ग्लासगो में 23 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया
- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष और सीईओ ने भारत और गुजरात के साथ उत्साहपूर्ण सहयोग से शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को शानदार सफलता मिलने की अपेक्षा व्यक्त की
- गुजरात की यात्रा के दौरान टीम अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और एकतानगर में आयोजित होने वाले सीडब्ल्यूजी 2030 के खेल स्थलों का साइट विजिट करेगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात में अहमदाबाद में 2030 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की अहमदाबाद सहित कई शहरों में जोरों शोरों से चल रही पूर्व तैयारियों के निरीक्षण तथा अध्ययन के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम पहली बार गुजरात की आधिकारिक यात्रा पर आई है।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इस टीम के पांच सदस्य इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान गुजरात में ठहरेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट से इस प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात यात्रा की शुरुआत की। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड रुकारे और सीईओ सुश्री केटी सैडलेयर ने गुजरात में उन्हें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए टाइम बाउंड, क्वालिटेटिव तथा इफेक्टिव प्लानिंग के मंत्र को साकार करते हुए शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए टीमवर्क से कार्य करते हुए इन खेलों का भव्य आयोजन करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।

श्री डोनाल्ड ने उल्लेख करते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में आयोजित होने जा रहे हैं, ऐसे में गुजरात को मिला इसका मेजबान पद अत्यंत गौरवपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और खेलों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को विश्वास दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से उपलब्ध कराएगी।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष और सीईओ ने आगामी जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को देखने और वहां के कार्य-प्रबंधन के अध्ययन तथा निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि गुजरात का प्रतिनिधिमंडल ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भाग लेगा।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट टीम के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड रुकारे ने गुजरात में आयोजित होने वाले 2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स को सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने वाला खेल उत्सव बनाने के लिए पारस्परिक टीमवर्क से कार्य करने की उत्सुकता दर्शाई।

गुजरात की इस यात्रा के दौरान कॉमनवेल्थ स्पोर्ट डेलीगेशन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के खेल स्थलों; अहमदाबाद का वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स, नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, ईकेए एरेना तथा वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम और एकता नगर - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पूर्व तैयारियों के निरीक्षण और अध्ययन के लिए साइट विजिट करेगा।

इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ प्रधान सचिव श्री अश्विनी कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात के महानिदेशक श्री वाळा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा असारवा–आगरा कैंट असारवा विशेष ट्रेन का नियमितीकरण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 01920/01919 असारवा–आगरा कैंट–असारवा स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अब सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी, जिससे हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा तथा रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस निर्णय के अंतर्गत ट्रेन संख्या 01920/01919 को नियमित ट्रेन संख्या 20177/20178 असारवा–आगरा कैंट–असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 20177 (असारवा–आगरा कैंट) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 से, सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार एवं बुधवार को छोड़कर) असारवा से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:15 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 20178 (आगरा कैंट–असारवा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिनांक 08 अप्रैल, 2026 से, सप्ताह में 5 दिन (सोमवार एवं मंगलवार को छोड़कर) आगरा कैंट से 18:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:00 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं बयाना जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर एवं जनरल सेकंड श्रेणी के कोच शामिल होंगे।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

सारंडा के जंगल में प्रकृति बनी काल, आंधी-तूफान में पेड़ गिरने से कोबरा जवान शहीद

(जीएनएस)। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने और संवेदनशील सारंडा जंगल से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के अभियान में जुटे सुरक्षाबलों के लिए इस बार दुश्मन कोई नक्सली नहीं, बल्कि प्रकृति का प्रकोप बन गया। मंगलवार देर रात अचानक आए तेज आंधी-तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि एक बहादुर जवान की जान चली गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल, Central Reserve Police Force (CRPF) की कोबरा बटालियन सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ एक सघन सर्च ऑपरेशन चला रही थी। यह इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है, जहां सुरक्षाबल लगातार जोखिम उठाकर अभियान चला रहे हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान चाईबासा क्षेत्र के बाबू डेरा कैंप के पास जवान तैनात थे कि अचानक मौसम ने करवट बदल ली।

रात के अंधेरे में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आंधी के बीच

एक विशाल पेड़ अचानक कैंप के पास आ गिरा, जिसकी चपेट में आकर कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी जवानों ने तुरंत उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रांची एयरलिफ्ट किया गया, जहां अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह वीर जवान जिंदगी की जंग हार गया और देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। राकेश कुमार का बलिदान इस बात की याद दिलाता है कि सुरक्षा बलों के जवान हर पल कितने जोखिमों के बीच देश की रक्षा करते हैं—चाहे वह दुश्मन की गोली हो या प्रकृति का प्रहार।

शहीद राकेश कुमार मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर प्रखंड स्थित धमनी गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग अपने इस वीर सपूत की शहादत पर गर्व भी कर रहे हैं और गमगीन भी हैं।

रांची स्थित CRPF कैंप में शहीद जवान को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह पल न केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए भावुक कर देने वाला होगा। इस घटना से महज 48 घंटे पहले भी इसी इलाके में एक और गंभीर घटना हुई थी। 6 अप्रैल को नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान छोटानागरा थाना क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कोबरा 205 बटालियन के जवान अनुज कुमार घायल हो गए थे। उन्हें भी तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इन दोनों घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि सारंडा क्षेत्र में अभियान कितना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है।

सारंडा का जंगल एशिया के सबसे घने साल वन क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां प्राकृतिक परिस्थितियां भी बेहद कठिन हैं। यहां ऊंचे-ऊंचे पेड़, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और अचानक बदलता मौसम सुरक्षाबलों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसके बावजूद जवान लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में जुटे हैं।

राकेश कुमार की शहादत केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस और समर्पण की प्रतीक है, जो हर भारतीय सैनिक के भीतर होता है। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और देश उनके इस सर्वोच्च त्याग को कभी नहीं भूल पाएगा।

पोरबंदर – आसनसोल के बीच 13 अप्रैल से प्रत्येक सोमवार को चलेगी "साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन",टिकटों की बुकिंग 10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से प्रारंभ होगी

(जीएनएस)। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अतिरिक्त यात्री सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के अंतर्गत विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन विशेष किराया (Special Fare) पर संचालित की जाएगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा पोरबंदर और आसनसोल के बीच "साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन" संचालित की जाएगी। यह सेवा अप्रैल 2026 से जून 2026 के मध्य दोनों दिशाओं में कुल 12-12 फेरों के साथ चलाई जाएगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

ट्रेन नंबर 09205 पोरबंदर – आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल 13 अप्रैल, 2026 से 29 जून, 2026 तक संचालित होगी।

यह ट्रेन पोरबंदर से प्रत्येक सोमवार को सुबह 8.50 बजे प्रस्थान कर बुधवार को सुबह 6.45 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 09206 आसनसोल – पोरबंदर साप्ताहिक स्पेशल 15 अप्रैल, 2026 से 01 जुलाई, 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन आसनसोल से प्रत्येक बुधवार को रात्रि 23.05 बजे प्रस्थान कर शुक्रवार को रात्रि 21.50 बजे पोरबंदर पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भाणवड, लालपुर जाम, जामनगर, हापा, राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर जं., विरमगाम, अहमदाबाद, आणंद, छायापुरी, गोधरा जं., रतलाम, नागदा जं., उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, ललितपुर, विरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जं., गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ओन सोन, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन गोमो, धनबाद जं. स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर तथा जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन नंबर 09205 के लिए टिकटों की बुकिंग 10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रीगण ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सेवा का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाएं।

"50 लाख भेजो, नहीं तो कान काट देंगे"-विदेश नौकरी के नाम पर युवक को इथियोपिया में बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला

(जीएनएस)। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से सामने आया यह मामला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि उन हजारों युवाओं और उनके परिवारों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाने का सपना देखते हैं। एक सुनियोजित तरीके से रचे गए इस जाल में फंसकर एक युवक आज हजारों किलोमीटर दूर Ethiopia में बंधक बना हुआ है और उसके बदले उसके परिवार से भारी-भरकम फिरौती मांगी जा रही है।

घटना की शुरुआत एक साधारण से सपने से हुई—विदेश जाकर बेहतर नौकरी पाने का सपना। गदरपुर के अब्दुल्लानगर निवासी रोहित कुमार को South Korea भेजने का लालच दिया गया। मुख्य आरोपी हिमांशु शर्मा, जिसने खुद को एक भरोसेमंद एजेंट बताया, ने परिवार को विश्वास दिलाया कि पूरी प्रक्रिया कानूनी और सुरक्षित तरीके से पूरी की जाएगी। परिवार को यकीन दिलाया गया कि रोहित जल्द ही दक्षिण कोरिया

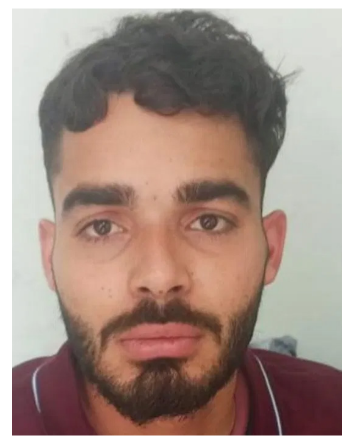

पहुंचकर अच्छी नौकरी शुरू कर देगा।

इस "सपने" की कीमत 15 लाख रुपये तय की गई, जिसमें से 5 लाख 65 हजार रुपये पहले ही आरोपी को दे दिए गए। यहीं से धोखे की असली कहानी शुरू होती है। साउथ कोरिया भेजने के बजाय रोहित को पहले Bangkok, फिर Sharjah और Dubai होते हुए अंततः इथियोपिया भेज दिया गया। यह पूरा रूट इस बात की ओर इशारा करता है कि मामला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है।

5 अप्रैल 2026 को इथियोपिया पहुंचने के बाद रोहित का परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसके बाद जो सामने आया, उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। परिजनों को कुछ तस्वीरें मिलीं, जिनमें रोहित का मुंह बंधा हुआ था और शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। यह तस्वीरें इस बात का प्रमाण थीं कि उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।

इसके बाद परिवार के पास कॉल और मैसेज आने लगे, जिनमें पहले 80 लाख रुपये की मांग की गई। बाद में यह रकम 50 लाख रुपये कर दी गई और एक QR कोड भेजकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। कॉल रिकॉर्डिंग में अपराधियों ने साफ धमकी दी—"अगर पैसे नहीं भेजे, तो रोहित के दोनों कान काट दिए जाएंगे।" यह धमकी न केवल अमानवीय है, बल्कि इस पूरे गिरोह की क्रूरता को भी उजागर करती है। परिवार का आरोप है कि यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का है। हिमांशु शर्मा के साथ अभिमन्यु, श्वेता, त्रिलोचन सिंह, मनदीप और अन्य अज्ञात लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गदरपुर के गूलरभोज रोड स्थित पपनेजा कॉलोनी के पास "इंट्रैको" नाम से एक कार्यालय चलाया जा रहा था, जहां से विदेश भेजने के नाम पर इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे फर्जी एजेंट इतने खुलेआम कैसे काम कर रहे हैं। बेरोजगारी और बेहतर अवसरों की तलाश में युवा अक्सर बिना पूरी जांच-पड़ताल के ऐसे एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें और उनके परिवारों को भुगतना पड़ता है।

जितेंद्र कुमार जयंत ने आज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अहमदाबाद के सलाहकार जनसंपर्क के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे पर वर्ष 1992 में सीधे जनसंपर्क विभाग में इंदौर में पदभार ग्रहण किया था तत्पश्चात जो जून 1996 में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जयपुर मंडल पर नियुक्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा के मूल निवासी जयंत ने अपनी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री तथा आगरा कॉलेज आगरा से विधि स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात के.एम. हिंदी इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ़ मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेने के पश्चात रेलवे में पदार्पण किया था । जयंत IRCTC अहमदाबाद में बतौर पुनः नियोजन के आधार पर नियुक्त किया गया है, वह 31 अगस्त 2024 में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल से वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी "ग्रुप ए" के रूप में सेवा निवृत हुए थे ।

जयंत का आईआरसीटीसी अहमदाबाद में

पद ग्रहण करने के पश्चात नई दिल्ली स्तर , मुंबई मुख्यालय स्तर तथा अहमदाबाद क्षेत्रीय स्तर पर आईआरसीटीसी के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जिससे आम जन समुदाय को सही जानकारी और भरपूर फायदा मिल सके।

पश्चिम रेलवे
भावनगर मण्डल

सिग्नलिंग गियर / सामग्री की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण

सं. डबल्यू/118/नि.आ.सू./ई-निविदा/2026-27 / 2 / डब्ल्यूए; ई-निविदा आमंत्रित करने की नोटिस दिनांकः 06/04/2026; भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (S&T) पश्चिम रेलवे, भावनगर निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता हैं:- **निविदा क्रमांक :- DRM-SnT-BVP-Sig02of26-27** भावनगर मंडल: 21 एलसी गेटों के इंटरलॉकिंग के संबंध में सिग्नलिंग गियर/सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना, जिनमें से 47 गेटों का एटीवीयू 10000 से अधिक है। **(अनुमानित लागत: ₹ 94469541.42/-)** (रुपये नौ करोड़ चौंवालीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ इकतालीस रुपये बयालीस पैसे मात्र) बोली दाताओं को अधिक जानकारी के लिए केवल www.ireps.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं. **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 28/04/2026 को 15:00 बजे तक रहेगी.**

BVP 324

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

जयपुर में वीआईपी शादी बनी आम जनता के लिए मुसीबत, ट्रैफिक जाम पर प्रशासन सख्त-एक आईपीएस समेत छह अधिकारियों पर कार्रवाई

(जीएनएस)। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल शादी समारोह अब प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बन गया है। 9 मार्च को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस अधिकारी कोमल मीणा की शादी जहां राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बनी, वहीं इस आयोजन के कारण शहर की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीकर रोड पर लगे कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम ने न केवल यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

यह घटना केवल एक शादी समारोह तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने यह दिखा दिया कि किस तरह वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान आम नागरिकों की सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आईपीएस अधिकारी सहित छह पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब

किया है और कुछ के तबादले भी कर दिए गए हैं। शादी समारोह जयपुर के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा क्षेत्र के एक रिसॉर्ट में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। वीआईपी मूवमेंट के चलते पहले से ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा हुआ था, लेकिन उचित प्रबंधन के अभाव में यह स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई। नतीजतन, सीकर रोड और आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें आम लोगों के साथ-साथ कई वीआईपी मेहमान भी फंस गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जाम इतना गंभीर था कि लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन को पहले से इस बड़े आयोजन की जानकारी थी, इसके बावजूद ट्रैफिक डायवर्जन या वैकल्पिक मार्गों की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई।

वायरलेस पर लगातार संदेश भेजे जाने के बावजूद मौके पर तैनात पुलिसकर्मी जाम को नियंत्रित करने में विफल रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि न केवल योजना बनाने में चूक हुई, बल्कि मौके पर तैनात अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी धीमी और अप्रभावी रही। यही कारण है कि यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा बन गया है। घटना के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल सीपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश को सौंपी गई, जिन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजी। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ट्रैफिक प्रबंधन में लापरवाही और समन्वय की कमी को उजागर किया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस टीम ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। जिन अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार माना गया है, उनमें एसीपी चोमू आईपीएस उषा यादव, एसीपी ट्रैफिक किशोर सिंह भदोरिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मंजू चौधरी, संपत राज, नवरत्न धौलिया और हरमाड़ा थाना अधिकारी उदय सिंह शामिल हैं। इस मामले में सबसे बड़ा कदम एसीपी चोमू उषा यादव के तबादले के रूप में सामने आया है, जिन्हें हाड़ी रानी बटालियन का कमांडेंट बना दिया गया है। इसके अलावा जयपुर डीसीपी ट्रैफिक का भी तबादला किया जा चुका है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि प्रशासन इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है।

“गुजरातियों का अपमान बर्दाश्त नहीं”: खड़गे के बयान पर सूरत से भाजपा का तीखा पलटवार, सियासत गरमाई

(जीएनएस)। सूरत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कथित बयान को लेकर गुजरात की राजनीति में तेज हलचल मच गई है। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरातियों के सम्मान पर सीधा हमला बताया है। सूरत में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसे “विभाजनकारी राजनीति” करार दिया। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, बल्कि चुनावी रणनीतियों और बयानबाजी की सीमाओं पर भी बहस छेड़ दी है। भाजपा के सूरत महानगर मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात भाजपा की प्रदेश सह-प्रवक्ता हेमालीबेन बोघावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि खड़गे का बयान पार्टी की “गुजरात विरोधी मानसिकता” को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास ही गुजरात और यहां के लोगों के योगदान को कमतर आंकने का रहा है। हेमालीबेन बोघावाला ने कहा कि गुजरात देश के विकास में हमेशा अग्रणी रहा है। व्यापार, उद्योग, नवाचार और राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में गुजरातियों ने जो योगदान दिया है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी न केवल राज्य के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी कमजोर करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुजरात की जनता अपनी अस्मिता पर आंच आने नहीं देगी और ऐसे बयानों का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरत महानगर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल ने भी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि

इस तरह के बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए समाज को बांटने वाली राजनीति कर रही है। परेश पटेल ने कहा कि गुजरातियों ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत की पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी राज्य या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की कि वह इस बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और भविष्य में इस तरह की भाषा से परहेज करे।

इस पूरे विवाद ने राजनीतिक हलकों में एक बड़ी बहस को जन्म दिया है कि क्या चुनावी राजनीति में इस तरह की बयानबाजी उचित है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में विचारों की भिन्नता स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी समुदाय या राज्य की पहचान को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इससे सामाजिक ताना-बाना भी प्रभावित हो सकता है।

भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उनके अनुसार, पार्टी को समझना चाहिए कि देश की विविधता उसकी ताकत है और इसे कमजोर करने की कोशिश करना राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वह नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति छोड़कर विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे।

इस मामले में कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। खासकर ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में चुनावी माहौल बना हुआ है, इस तरह के विवाद राजनीतिक दलों के लिए अवसर और चुनौती दोनों बन सकते हैं। सूरत से उठी यह राजनीतिक प्रतिक्रिया अब राज्य स्तर से आगे बढ़कर राष्ट्रीय बहस का रूप लेती दिखाई दे रही है। भाजपा इस मुद्दे को गुजरात के गौरव और अस्मिता से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस के लिए यह एक संवेदनशील स्थिति बन गई है, जहां उसे अपने बयान और उसकी व्याख्या को लेकर स्पष्टता देनी पड़ सकती है।

कुल मिलाकर, यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक संवाद की मर्यादा, चुनावी रणनीति और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या इससे राजनीतिक दल कोई सबक लेते हैं या फिर यह भी चुनावी शोर-शराबे में खो जाता है।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ऐतिहासिक उपलब्धि, 1360 टन का सबसे भारी पोर्टल बीम सफलतापूर्वक लॉन्च

(जीएनएस)। अहमदाबाद। देश की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। मणिनगर के पास अहमदाबाद–वडोदरा रेलवे लाइन के ऊपर करीब 1360 मीट्रिक टन वजनी प्रीकास्ट-प्रेस्ट्रेस्ड पोर्टल बीम (गर्डर) की सफल लॉन्चिंग पूरी कर ली गई है। यह अब तक भारतीय रेलवे अवसंरचना पर स्थापित किए गए सबसे भारी ढांचों में से एक माना जा रहा है, जिसने परियोजना की तकनीकी क्षमता और सटीकता को नई पहचान दी है।

यह विशाल पोर्टल बीम करीब 34 मीटर लंबा है और इसका क्रॉस-सेक्शन 5.5 मीटर × 4.5 मीटर है। इसे प्रीकास्ट

तकनीक के तहत साइट पर ही तैयार किया गया और एकीकृत भारी इकाई के रूप में स्थापित किया गया। मणिनगर रेलवे स्टेशन के पास ऐसे कुल पांच बीम लगाए जाने की योजना है, जो इस पूरे सेक्शन में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए मजबूत संरचनात्मक आधार प्रदान करेंगे।

इस जटिल इंजीनियरिंग कार्य की सबसे खास बात इसकी समय-सीमा रही। जहां पहले इसी प्रक्रिया के लिए करीब 6 महीने तक लंबे कॉशन ऑर्डर और लगभग 9 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता आंकी गई थी, वहीं उन्नत योजना और बेहतर समन्वय के चलते इसे महज 3.5 घंटे में पूरा कर लिया गया। यह उपलब्धि न केवल समय प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि रेलवे संचालन को न्यूनतम प्रभावित करते हुए बड़े स्तर का निर्माण कार्य पूरा करने की क्षमता को भी दर्शाती है। इस ऑपरेशन में 2200 मीट्रिक टन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन का उपयोग किया गया, जिसे 260 टन के स्टैंडबाय क्रेन, 80 टन के अतिरिक्त क्रेन, मैन लिफ्टर और एंकरिंग फ्रेम जैसे उपकरणों का समर्थन प्राप्त था। पूरी लिफ्टिंग प्रक्रिया में 75 मिमी व्यास के प्रेस्ट्रेस्ड मैकएलॉय बार, विशेष लिफ्टिंग बीम और हेवी-ड्यूटी स्लिंग्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे इतने भारी ढांचे को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से उठाया जा सका। यह कार्य कई जटिल चुनौतियों से भरा हुआ था। सीमित कार्यक्षेत्र, ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरण (OHE), और एक साथ सक्रिय कई रेलवे लाइनों के बीच काम करना बेहद कठिन था। इसके अलावा, करीब 15 मीटर की ऊंचाई पर इतनी भारी संरचना को सटीकता के साथ स्थापित करना उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कौशल और तकनीकी दक्षता की मांग करता है। इस दौरान हवा की गति की लगातार निगरानी, रिगिंग सिस्टम की कड़ी जांच, बैकअप लिफ्टिंग सिस्टम की तैनाती और सटीक सर्वे व एलाइनमेंट नियंत्रण जैसे कई सुरक्षा उपाय अपनाए गए। इस पूरे अभियान में Indian Railways के साथ रीयल-टाइम समन्वय भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा, जिससे ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के दौरान कार्य को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। यह उपलब्धि न केवल बुलेट ट्रेन परियोजना की गति को और तेज करेगी, बल्कि भारत में आधुनिक अवसंरचना निर्माण के स्तर को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। यह स्पष्ट संकेत है कि देश अब अत्याधुनिक तकनीक और कुशल प्रबंधन के दम पर विश्वस्तरीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सूरत नगर निगम चुनाव में टिकटों पर मंथन तेज, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आज हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा

(जीएनएस)। सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां टिकट वितरण को लेकर सभी प्रमुख दलों के भीतर गहन मंथन जारी है। इसी क्रम में Bharatiya Janata Party ने गुरुवार 9 अप्रैल को अपने प्रदेश संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी और इसके बाद देर रात तक उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है।

बैठक से पहले पार्टी ने समन्वय को मजबूत करने के लिए सांसदों और विधायकों की एक अलग बैठक भी निर्धारित की है। इस बैठक में सूरत के प्रभारी मंत्री और राज्य के वित्त मंत्री Kanubhai Desai की मौजूदगी विशेष रूप से अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस समन्वय बैठक में विभिन्न वार्डों की राजनीतिक स्थिति, स्थानीय समीकरण और दावेदारों की ताकत का आकलन कर अंतिम रणनीति तय की जाएगी।

सूरत नगर निगम के 30 वार्डों के लिए कुल 120 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है, जो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है। कई वार्डों में टिकट के लिए दावेदारों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिससे पार्टी नेतृत्व के सामने संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। पार्टी इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि उम्मीदवार चयन में स्थानीय लोकप्रियता, संगठन के प्रति निष्ठा और जीत की संभावना जैसे सभी पहलुओं को संतुलित किया जाए।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने पहले ही अपने पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) की टीमें सूरत भेज दी थीं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात कर हर वार्ड के लिए तीन से चार नामों का पैनल तैयार किया है। अब इन्हीं नामों पर संसदीय बोर्ड की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

चुनावी कार्यक्रम भी तय हो चुका है, जिसके अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल है। इसके बाद 26 अप्रैल को मतदान होगा और 28 अप्रैल को मतगणना के जरिए चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों को नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय ही उपलब्ध होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सूरत नगर निगम चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि यह उसका पारंपरिक मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में पार्टी कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और हर सीट पर मजबूत और जीतने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है।

कुल मिलाकर, आज होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक सूरत की सियासत की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। देर रात तक आने वाली उम्मीदवारों की सूची पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो चुनावी मुकाबले की तस्वीर को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी।

भारत मे पहली बार 2200 MT क्रेन का कमाल, अहमदाबाद में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर पर रचा इतिहास

1360 टन वजनी पोर्टल बीम का सफल लॉंच,मणिनगर–अहमदाबाद रेलखंड पर बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में मुम्बई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना के अंतर्गत आज मणिनगर–अहमदाबाद रेलखंड पर अत्यंत जटिल एवं उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस क्रम में किमी 497 (BKC/Mumbai से दूरी) पर स्थित पियर संख्या 05 पर प्रीकास्ट आरसीसी पोर्टल बीम का सफल प्रक्षेपण (Launching) किया गया, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है।

इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश तथा PCPM/NHSRCL, अहमदाबाद श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति एवं निगरानी में कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

उक्त पोर्टल बीम अत्यंत विशाल एवं भारी संरचना है, जिसका वजन लगभग 1360 टन है। इसकी लंबाई 34 मीटर, चौड़ाई 5.5 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इसे M50 ग्रेड कंक्रीट से निर्मित किया गया है, जिससे इसकी संरचनात्मक मजबूती

एवं दीर्घायु सुनिश्चित होती है।

इस जटिल कार्य के निष्पादन हेतु 2200 टन क्षमता वाली अत्याधुनिक क्रॉलर क्रेन (SANY SCC38000TM) का उपयोग किया गया, जिसका भारतीय रेलवे में प्रथम बार प्रयोग किया गया है। यह क्रेन उच्च स्तरीय सुपर-लिफ्ट तकनीक से युक्त है, जो भारी-भरकम संरचनाओं को सुरक्षित एवं नियंत्रित ढंग से स्थापित करने में सक्षम है।

इस विशाल क्रेन के विभिन्न हिस्सों को लगभग 110 ट्रेलरों के माध्यम से साइट तक पहुँचाया गया, जहाँ विशेषज्ञ इंजीनियरों की निगरानी में सटीक एवं चरणबद्ध तरीके से असेम्बली कार्य संपन्न किया गया। यह प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत जटिल एवं तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी। इस उन्नत तकनीक एवं सुव्यवस्थित योजना के उपयोग से न केवल कार्य की दक्षता में वृद्धि हुई, बल्कि समय की उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित हुई तथा उच्चतम सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया।

कार्य के सफल निष्पादन हेतु मणिनगर–अहमदाबाद रेलखंड पर लगभग 03 घंटे 30 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया। इस अवधि के दौरान सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया गया तथा ब्लॉक समाप्ति के पश्चात रेल यातायात को सुचारु रूप से बहाल कर दिया गया।

इस प्रकार के जटिल कार्य के लिए पूर्व नियोजित चरणबद्ध तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें प्री-कास्टिंग, लिफ्टर अटैचमेंट, ट्रायल लिफ्टिंग, क्रेन पोजिशनिंग, सुपर-लिफ्ट ऑपरेशन, बीम लिफ्टिंग एवं अंतिम स्थापना जैसे सभी महत्वपूर्ण चरणों का समुचित समन्वय किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्य क्षेत्र में उपस्थित ओएचई (OHE), सिग्नलिंग उपकरणों एवं अन्य अवरोधों का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी विस्थापन एवं पुनर्स्थापन सुनिश्चित किया गया।

परियोजना के आगामी चरणों में इसी प्रकार के अन्य पोर्टल बीमों—P06, P07, P08 एवं P09—का प्रक्षेपण भी निर्धारित है, जिन्हें लगभग प्रत्येक 6 दिनों के अंतराल पर क्रमिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इन सभी पोर्टल बीमों का वजन लगभग 1070 टन से 1110 टन के मध्य है तथा इन्हें उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया है।

मुम्बई से आने वाली बुलेट ट्रेन का एलाइन्मेंट मणिनगर क्षेत्र में पारंपरिक रेलवे के तीनों ट्रैकों (UP, DN एवं 3rd Line) को क्रॉस करते हुए ओल्ड रेलवे कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड, कांकरीया क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा आगे अहमदाबाद स्टेशन होते हुए साबरमती मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब की दिशा में अग्रसर होता है।

इस संदर्भ में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट के माध्यम से उल्लेख किया कि—

“गुजरात के मणिनगर में बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत सबसे भारी गिर्डर्स में से एक का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसका वजन लगभग 1,360 मीट्रिक टन है तथा इसे मात्र 3.5 घंटे के निर्धारित समय में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।”

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की अत्याधुनिक हेवी-लिफ्ट तकनीक के उपयोग से पारंपरिक विधियों की तुलना में कार्य की गति, सटीकता एवं सुरक्षा स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे एवं हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत आधुनिक अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

सूरत में ‘टेक्सटाइल अवाड्र्स’ की घोषणा, 45 कैटेगरी में उत्कृष्ट कार्यों को मिलेगा सम्मान

(जीएनएस)। सूरत। देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब सूरत में उद्योग को नई दिशा देने और इनोवेशन व सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry ने मई 2026 में ‘टेक्सटाइल अवाड्र्स’ आयोजित करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत कुल 45 विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा।

चैंबर के अध्यक्ष Nikhil Madrasi ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अवाड्र्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी प्रमुख सेगमेंट—फैब्रिक, यार्न, गारमेंट्स, मेड-अप्स, प्रोसेसिंग, डाइंग, ट्रेडिंग और रिटेलिंग—को कवर करेंगे। इसका उद्देश्य पूरे सेक्टर को एक साथ प्रोत्साहित करना और व्यापक विकास सुनिश्चित करना है।

अवाड्र्स की प्रमुख कैटेगरी में प्रोडक्ट इनोवेशन, बेस्ट अल्टरनेट मटीरियल यूज़, एक्सपोर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, नई तकनीकों को अपनाने में श्रेष्ठता, बेस्ट एचआर प्रैक्टिस (कर्मचारी कल्याण) और टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियां शामिल हैं। इन श्रेणियों के जरिए उद्योग में गुणवत्ता सुधार, आधुनिक तकनीक के उपयोग और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवार्ड में बुनकर, स्पिनर, डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल और मेड-अप्स सेक्टर के उद्यमी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ चयनित श्रेणियों में ट्रेडर्स को भी भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे उद्योग के हर स्तर को प्रतिनिधित्व मिल सके।

चैंबर का मानना है कि यह पहल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और कंपनियों को गुणवत्ता, नवाचार और सस्टेनेबिलिटी के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही, उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को पहचान मिलने से अन्य उद्योगों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कुल मिलाकर, ‘टेक्सटाइल अवाड्र्स 2026’ सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर और मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्रूड ऑयल वायदा 1920 रुपये लुढ़का: सोना वायदा में 3011 रुपये और चांदी वायदा में 14323 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 228650.6 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 35009.3 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 193641.19 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36813 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5382.12 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 23293.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 153550 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 154934 रुपये और नीचे में 152693 रुपये पर पहुंचकर, 150289 रुपये के पिछले बंद के सामने 3011 रुपये या 2 फीसदी बढ़कर 153300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 2754 रुपये या 2.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 122580 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 341 रुपये या 2.27 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15356 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मई वायदा 151000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153390 रुपये और नीचे में 151000 रुपये पर पहुंचकर, 3270 रुपये या 2.2 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152003 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 150999 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153697 रुपये और नीचे में 150999 रुपये पर पहुंचकर, 149023 रुपये के पिछले बंद के सामने 3431 रुपये या 2.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152454 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 240601 रुपये के भाव पर खूलकर, 246376 रुपये के दिन के उच्च और 240601 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 231348 रुपये के पिछले बंद के सामने 14323 रुपये या 6.19 फीसदी की मजबूती के साथ 245671 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 14463 रुपये या 6.18 फीसदी की बढ़त के साथ 248317 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 14448 रुपये या 6.18 फीसदी की मजबूती के साथ 248400 रुपये प्रति

▸▸ कॉटन वायदा में 110 रुपये और मेंथा तेल वायदा में 4.20 रुपये की नरमी: कपास वायदा 66 रुपये और इलायची वायदा 17 रुपये बढ़ा: कमोडिटी वायदाओं में 35009 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 193641 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 23293 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36813 पॉइंट के स्तर पर

किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 2787.30 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 26.5 रुपये या 2.29 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1186.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 1.35 रुपये या 0.41 फीसदी की तेजी के संग 330.35 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1 रुपये या 0.28 फीसदी औंधकर 354.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 30 पैसे या 0.15 फीसदी की नरमी के साथ 195.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8836.57 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 10243 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 10243 रुपये और नीचे में 8749 रुपये पर पहुंचकर, 1920 रुपये या 18 फीसदी औंधकर 8749 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1920 रुपये या 18 फीसदी की गिरावट के साथ 8747 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 262 रुपये के भाव पर खूलकर, 262 रुपये के दिन के उच्च और 253.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 269.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 14 रुपये या 5.19 फीसदी लुढ़ककर 255.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 13.8 रुपये या 5.11 फीसदी गिरकर 256.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 1051 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.20 रुपये या 0.41 फीसदी गिरकर 1019 रुपये प्रति किलो हुआ। कॉटन अप्रैल वायदा प्रति गांठ 28500 के भाव पर खूलकर, 110 रुपये या 0.38 फीसदी की नरमी के साथ 28500 रुपये के स्तर पर ही स्थिर रहा। जबकि कपास का अप्रैल वायदा प्रति 20 किलो 1651 रुपये के स्तर पर खूलकर, ऊपर में 1716 रुपये और नीचे में 1651 रुपये के स्तर को छूकर 66 रुपये या 4 फीसदी की बढ़त के साथ 1716 रुपये पर पहुँचा। इलायची का अप्रैल वायदा प्रति किलो 2570 रुपये के भाव पर खूलकर, ऊपर में 2670 रुपये और नीचे में 2570 रुपये के स्तर पर पहुँचकर 17 रुपये या 0.64 फीसदी की वृद्धि के साथ 2669 रुपये हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16078.73 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7214.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1963.40 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 388.92 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 13.18 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 415.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7127.04 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1674.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.07 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8230 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 49212 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 24982 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 368474 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 54631 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6993 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19383 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 75474 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15633 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 41818 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 36813 पॉइंट पर खूलकर, 36813 के उच्च और 36813 के नीचले स्तर को छूकर, 1040 पॉइंट बढ़कर 36813 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 1059.9 रुपये की गिरावट के साथ 185 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.65 रुपये की गिरावट के साथ 10.3 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 121 रुपये की बढ़त के साथ 582 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 177.5 रुपये की बढ़त के साथ 882 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.07 रुपये की बढ़त के साथ 19.15 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो बिना बदलाव के 4.88 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 148.5 रुपये की बढ़त के साथ